

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2020—माघ 18, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-24/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2019/3460 दिनांक 25-12-2019 अनुसार नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम निर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08-12-2019 को हो जाने के कारण पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन दिनांक 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन हेतु दिनांक 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

3. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5 : राज्य शासन एतद्वारा, यह भी घोषित करता है कि, नगर पंचायत दोरनापाल जिला-सुकमा के वार्ड क्रमांक 14 के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में पार्षद पद के प्रत्यादिष्ट निर्वाचन हेतु दि. 21-01-2020 दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 8-21/2005/10-2.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-02-2014 को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम 2015 के नियम 3, 6 एवं 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

1. **अध्यक्ष**
श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड — अध्यक्ष
2. **पदेन/शासकीय सदस्य**
 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) छत्तीसगढ़ — सदस्य
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) — सदस्य
 3. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय — सदस्य
 4. कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा — सदस्य
 5. राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामांकित वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य सचिव
3. **विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्य**
 1. प्रो. एम.एल.नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल ऑफ लाईफ साइंसेस) पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर. — सदस्य
 2. संचालक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया — सदस्य
 3. संचालक, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया — सदस्य
 4. डॉ. फैयाज ए. खुदसर, वैज्ञानिक बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम — सदस्य
 5. श्री अशोक तिवारी (से.नि.) क्यूरेटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल. — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.क. (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित पद पर नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम व पदनाम	छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मण्डल (भा.प्र.से.) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.	अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक)
2.	श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर.	निदेशक (गैर-पूर्णकालिक)

2. उपरोक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 6-92/2019/वा.कर. (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक आयुक्त आबकारी को उपायुक्त आबकारी, के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में (वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 7600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री पी. एल. साहू, सहायक आयुक्त आबकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ मुख्यालय, जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ मुख्यालय, जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.

2. उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में लंबित याचिका क्रमांक WP (PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another. में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी.

3. उपरोक्त अधिकारी की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2019/एक/6, दिनांक 11 जून, 2019 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 की कंडिका 4.5 में प्राप्त अधिकारों के पालन में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 जनवरी 2020

क्रमांक 54/आर-66/2016/13/2.—विभागीय आदेश क्रमांक 2788/आर-66/2016/13/2 दिनांक 04-12-2019 एवं सहपठित आदेश 2835/आर-66/2016/13/2 दिनांक 09-12-2019 द्वारा श्री राजेश वर्मा आत्मज स्व. श्री बी. पी. वर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. श्री राजेश वर्मा आत्मज स्व. श्री बी. पी. वर्मा, डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त पद से त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01-01-2020 को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा आदेश जारी करने के दिनांक से श्री राजेश वर्मा आत्मज स्व. श्री बी. पी. वर्मा, को उक्त कंपनी के डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है।

3. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री एन. के. बिजौरा, आत्म. स्व. श्री एल. एल. बिजौरा, कार्यपालन निदेशक (संचा./संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड, रायपुर के डायरेक्टर, के पद पर नियुक्त करता है।

4. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टर श्री एन. के. बिजौरा, आत्मज स्व. श्री एल. एल. बिजौरा, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पद पर नियुक्त करता है।

5. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 1-06/2018/दो-गृह/भापुसे (पार्ट).—राज्य शासन, एतद्वारा श्री सूरज सिंह, (भापुसे-2015), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा को उनके वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुए नवगठित जिला गौरैला-पेंड्रा-मरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पुलिस) के रूप में संबद्ध करता है।

2. उक्त अधिकारी कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज बिलासपुर में संबद्ध रहकर नवीन जिले के विधिवत् प्रारंभ होने तक जिले से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे स्टाफ की व्यवस्था, फर्नीचर, वाहनों की व्यवस्था एवं अभिलेखों के हस्तांतरण आदि कार्य अविभाजित जिला बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर संपादित कराएंगे, ताकि नवगठित जिला प्रारंभ होने पर वहां कार्य संचालन में कोई कठिनाई न आयें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिषे, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

शुद्धि पत्रक

क्रमांक एफ 23-21/2014/20-3.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-11-2019 द्वारा राज्य शिक्षा स्थायी समिति में श्री राजेश शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, बड़ईपारा, रायपुर को नियम 3 (2) (दस) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का एक प्रतिनिधि के रूप में सदस्य घोषित किया गया है।

राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बड़ईपारा रायपुर के स्थान पर श्री राकेश शर्मा पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. खान, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मोहपुर प.ह.नं. 28	0.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सालहेभाट प.ह.नं. 13	4.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	कानागांव व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	बागोड प.ह.नं. 17	0.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	बागोड एनीकेट के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कुरिछीकुर प.ह.नं. 12	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	बांधापारा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कन्हनपुरी प.ह.नं. 18	2.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत लघु नहर क्रमांक 11 में निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/13/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	देवरीबालाजी प.ह.नं. 19	1.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/14/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	सोनपुर प.ह.नं. 18	0.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत माईनर नंबर 10 में निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	देवरीबालाजी प.ह.नं. 19	0.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/16/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	शाहवाड़ा प.ह.नं. 31	1.64	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	तारसगांव - शाहवाड़ा मार्ग के कि.मी. 5/6 में महानदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/16/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कन्हनपुरी प.ह.नं. 18	2.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत लघु नहर क्रमांक 10 में निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/17/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	मानिकपुर प.ह.नं. 19	2.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायी तट नहर निर्माण योजना अंतर्गत लघु नहर क्रमांक 09 में निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/19/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	तारसगांव प.ह.नं. 20	1.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	तारसगांव - शाहवाड़ा मार्ग के कि.मी. 5/6 में महानदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	सारवण्डी प.ह.नं. 25	0.58	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग, कांकेर.	कांकेर दुधावा मार्ग के कि.मी. 25/4 पर उच्च-स्तरीय सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक/26/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सिंगारभाट प.ह.नं. 12	0.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3554	0.049
3556	0.234
3519	0.081

रा.प्र.क्र. 8596/भू-अर्जन/02 अ/82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

योग

03	0.364
----	-------

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
 - (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-कसरा
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
 - (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-बुड़ार
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.517 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	637	0.086
3588	0.012	योग 08	0.517
3594	0.243	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कसरा, बुड़ार पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.	
3591	0.008		
3592	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
687	0.056		
688	0.052	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
686	0.052	डोमन सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्रमांक/913/क्षे.प.अ./2019.—आदेश क्रमांक खाद्य/धान उपार्जन/1009/2019 बिलासपुर, दिनांक 05-10-2019 द्वारा कस्टम मिलिंग के धान/चावल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामग्री परिवहन में लगे वाहनों को आवागमन में दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक शहर के अंदर के सभी मार्गों एवं बिल्हा से बिलासपुर मुख्य मार्ग, इंदिरा सेतु एवं तिफरा सेतु के दोनों तरफ 24 घंटे परिवहन करने की छूट प्रदान किया गया था.

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात बिलासपुर से चर्चा उपरांत आमजन की सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए मैं डॉ. संजय अलंग जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में पारित आदेश क्रमांक खाद्य/धान उपार्जन/1009/2019 बिलासपुर, दिनांक 05-10-2019 में आंशिक संशोधन करते हुए सुबह 09.30 से 10.30 एवं शाम 05.30 से 06.30 में महामाया चौक से लेकर मोतीलाल पेट्रोल पम्प, चक्ररभाठा रोड, मंगला चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक और व्यापार विहार रोड से महाराणा प्रताप चौक तक छूट प्रदान किये गये वाहनों को भी प्रतिबंधित करता हूं, शेष समय उक्त वाहनों को प्रदान की गई छूट यथावत् रहेगा.

डॉ. संजय अलंग,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5000.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/6816-6817, रायपुर दिनांक 16-01-2013 द्वारा श्री आर. के. चन्द्रा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक/8247/वित्त-1/न.क्र. 166/2019 दिनांक 29-10-2019 द्वारा श्री आर. के. चन्द्रा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का जिला जांजगीर स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर पदस्थ श्री वतन जाधव, कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र बेलरगांव, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.ख. नगरी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री आर. के. चन्द्रा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का जिला जांजगीर स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर पदस्थ श्री वतन जाधव, कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र बेलरगांव, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.ख. नगरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5002.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/3591-3592, रायपुर दिनांक 09-08-2018 द्वारा श्री राकेश कुमार जोशी, सहायक संचालक (कृषि) कोन्टा, जिला सुकमा को कृषि उपज मंडी समिति कोन्टा, जिला सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला सुकमा का पत्र क्रमांक/3586/स्टेनो/2019 दिनांक 14-10-2019 द्वारा श्री कैलाश नाथ मरकाम, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, सुकमा को कृषि उपज मंडी समिति कोन्टा, जिला सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री राकेश कुमार जोशी, सहायक संचालक (कृषि) कोन्टा, जिला सुकमा के स्थान पर श्री कैलाश नाथ मरकाम, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, सुकमा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोन्टा, जिला सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5122.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5474-5975, रायपुर दिनांक 30-12-2016 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनेन्द्रगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. (ध्वज-ब)

कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर का पत्र क्रमांक/8878/व.लि./भा.सा.धि./2019 बैकुण्ठपुर, दिनांक 08-11-2019 द्वारा श्री आर.पी. चौहान, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनेन्द्रगढ़, के स्थान पर श्री आर. पी. चौहान, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5124.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/7804-7805, रायपुर दिनांक 09-01-2018 द्वारा श्री रोविन्स कुजुर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज, जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज का ज्ञापन क्रमांक/284/स्टेनो/2019 बलरामपुर, दिनांक 18-11-2019 द्वारा श्री एन.एस.भगत, सहायक संचालक कृषि, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री रोविन्द कुजुर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि के स्थान पर श्री एन.एस.भगत, सहायक संचालक कृषि, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5418.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2018-19/1235, दिनांक 18-05-2016 द्वारा श्री के. आर. भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला महासमुंद का ज्ञापन क्रमांक/35/क/अ.अ.ऊ.शाखा/2019-20 दिनांक 15-11-2019 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला-महासमुंद में भारसाधक अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री के. आर. भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा के स्थान पर श्री डी.पी.पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पिथौरा जिला महासमुंद को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री के. आर. भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा के स्थान पर श्री डी. पी. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पिथौरा जिला महासमुंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा, जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5420.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1393, दिनांक 25-05-2018 द्वारा श्री एम.एस. ध्रुव, संयुक्त संचालक कृषि जगदलपुर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला बस्तर का पत्र क्रमांक/कले/मंडी/933/19 जगदलपुर, दिनांक 02-12-2019 द्वारा श्री कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर, जिला-बस्तर में भारसाधक अधिकारी के पद पर पदस्थ श्री एम. एस. ध्रुव, संयुक्त संचालक कृषि जगदलपुर के स्थान पर श्रीमती माधुरी सोम, डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एम.एस.ध्रुव, संयुक्त संचालक कृषि जगदलपुर के स्थान पर श्रीमती माधुरी सोम, डिप्टी कलेक्टर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर, जिला बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5422.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2314, दिनांक 30-06-2016 द्वारा श्री एन.एस. बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर जिला-नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला नारायणपुर का पत्र क्रमांक/स्था./भारसाधक अधि./2019-20/416 नारायणपुर, दिनांक 23-11-2019 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला-नारायणपुर में भारसाधक अधिकारी के पद पर पदस्थ श्री एस.एन.बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर का संविदा कार्यकाल दिनांक 31-10-2019 को समाप्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री एन. के. नागेश उप संचालक कृषि जिला नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एस. एन. बाजपेयी, डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर के स्थान पर श्री एन. के. नागेश उप संचालक कृषि जिला नारायणपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5704.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/587, दिनांक 26-04-2017 द्वारा श्री एस. के. प्रसाद, उपसंचालक कृषि सूरजपुर जिला सूरजपुर को कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला सूरजपुर का पत्र क्रमांक 6462/व.लि./2019 सूरजपुर दिनांक 07-12-2019 द्वारा श्री एस. के. प्रसाद, उपसंचालक कृषि सूरजपुर जिला सूरजपुर का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री दिनेश चंद्र कोसले, उपसंचालक कृषि सूरजपुर को कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एस. के. प्रसाद, उपसंचालक कृषि सूरजपुर के स्थान पर श्री दिनेश चंद्र कोसले, उपसंचालक कृषि सूरजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6256.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/1703, दिनांक 19-06-2019 द्वारा श्री जी. एस. धुर्वे, उपसंचालक कृषि को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला दुर्ग का पत्र क्रमांक/मंडी/स्था./भा.सा.अ.नि./2019-20/12873 दुर्ग दिनांक 30-12-2019 श्री जी. एस. धुर्वे, उपसंचालक कृषि दुर्ग का स्थानांतरण कार्यालय उपसंचालक कृषि राजनांदगांव होने के कारण श्री ए. के. बंजारा, उपसंचालक, कृषि दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री जी. एस. धुर्वे, उपसंचालक कृषि दुर्ग के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री ए. के. बंजारा, उपसंचालक, कृषि दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6258.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/15220, दिनांक 26-11-2016 द्वारा श्री एस. आर. डोंगरे, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति बसना जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला महासमुंद का ज्ञापन क्रमांक/37/क/अ.अ.ऊ.शाखा/2019-20 महासमुंद दिनांक 07-12-2019 श्री एस.आर.डोंगरे अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) का स्थानांतरण होने के कारण श्री परमानंद सामल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना जिला महासमुंद को कृषि उपज मंडी समिति बसना जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एस. आर. डोंगरे, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री परमानंद सामल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बसना जिला महासमुंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बसना जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6260.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5422, दिनांक 03-12-2019 द्वारा श्री एन. के. नागेश, उपसंचालक कृषि जिला नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर जिला नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर का पत्र क्रमांक/स्था./भारसाधक अधि./2019-20/472 नारायणपुर दिनांक 28-12-2019 द्वारा संलग्न कलेक्टर जिला नारायणपुर के अनुशंसा अनुसार श्री एन. के. नागेश, उपसंचालक कृषि जिला नारायणपुर का स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री पी. डी. मंडावी, सहायक संचालक कृषि जिला नारायणपुर को मंडी समिति नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री एन. के. नागेश, उपसंचालक कृषि जिला नारायणपुर के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री पी. डी. मंडावी, सहायक संचालक कृषि जिला नारायणपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर जिला नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6262.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-8/1/32(2)/भा.अधि./2017-18/8048, दिनांक 01-01-2018 द्वारा श्री देवेन्द्र रामटेके, उपसंचालक कृषि जिला कोरिया को कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, कृषि कोरिया बैकुण्ठपुर का पत्र क्रमांक/75/व.लि./भा.सा.धि./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 07-01-2020 प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जिला कोरिया छ.ग. को कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री देवेन्द्र रामटेके, उपसंचालक कृषि जिला कोरिया के स्थान पर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जिला कोरिया छ.ग. को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्रमांक 7794/चेकर/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 3698 तीन-6-7/2000 दिनांक 12-04-2018 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री पंकज आलोक तिकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग. दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा।

No. 7794/Checker/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 3698/III-6-7/2000, dated 12-04-2018 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Pankaj Alok Tirkey, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
Deepak Kumar Tiwari, I/c Registrar General.